साप्ताहिक

डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 26 जुलाई 2021, वर्ष-7, अंक-17

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 8 रुपए

खजाना भरने शिवराज की अनूठी पहल, बाढ़, जल संकट की समस्या होगी दूर

बांधों की गाद से होगा बंफर फसल उत्पादन

» बांधों की रेत से होगी अब अरबों रुपए की कमाई

» प्रदेश में सालभर होगा बिजली का भरपूर उत्पादन

अरविंद मिश्र, भोपाल

मध्यप्रदेश प्राकृतिक संसाधनों और खनिज संपदा से परिपूर्ण प्रदेश है। शिवराज सिंह चौहान जबसे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों और खनिज संपदा के संरक्षण के लिए क्रांतिकारी कदम उठाया है। इसी कड़ी में उनकी सरकार ने प्रदेश के चार बड़े बांधों से रेत व सिल्ट (गाद) निकालने का ठेका देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। पहले चरण में रानी अवंतिबाई सागर बरगी, तवा, इंदिरा सागर और बाणसागर बांध का ठेका दिया जाएगा। इन चारों बांधों से जो गाद निकाली जाएगी, उसमें 15 से लेकर 40 प्रतिशत तक रेत मिल सकती है। गाद किसानों को दी जाएगी, जिसे वे खेतों में डालेंगे। इससे भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी और फसल का उत्पादन भी बढ़ जाएगा। वहीं, इससे जो रेत प्राप्त होगी, उससे शासन को राजस्व मिलेगा। ठेका 15 से 25 साल के लिए उस कंपनी को दिया जाएगा, जिसका तीन साल का टर्नओवर 500 करोड़ रुपए होगा। अनुमान है कि सरकार को इससे सालाना 300 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। जलाशयों से सिल्ट व रेत निकालने से बांधों की उम्र बढ़ेगी और पर्यावरण संतुलित होने के साथ-साथ जलाशय में पानी भरने की क्षमता भी बढ़ेगी। जल संसाधन विभाग के मुताबिक बांधों में गाद जमने से जल भंडारण क्षमता कम हो जाती है। इसके चलते रेत व सिल्ट निकालने का प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा गया था। इसका असर सिंचाई और पेयजल व्यवस्था से जुड़ी योजनाओं पर पड़ता है। जलाशयों के अलग-अलग ठेके होंगे। यह काम ऐसी कंपनी को दिया जाएगा, जिसे इस क्षेत्र में काम करने का अनुभव हो।

चार बांधों का चयन

पहले चरण में रानी अवंतिबाई सागर बरगी, तवा, इंदिरा सागर और बाणसागर बांध का ठेका दिया जाएगा। इन चारों बांधों से जो गाद निकाली जाएगी, उसमें 15 से लेकर 40 प्रतिशत तक रेत मिल सकती है। यह फैसला हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया है।

मप्र के बांधों में रेतीला सोना

मध्यप्रदेश के बांधों की तलहटी में रेतीला सोना भरा पड़ा है। मप्र सरकार ने बांधों से रेत और गाद निकालने का जो निर्णय लिया है, वह कमाई का बड़ा स्रोत बन सकता है। विशेषज्ञों का कहना है की बांधों की तलहटी में अच्छी क्वालिटी की रेत है जो महंगे दामों में बिक सकती है।

देश का पहला राज्य मप्र कर रहा अनोखा प्रयोग

अब फसल नहीं होगी चौपट

प्रदेश के राजस्व विभाग के अनुसार विगत वर्ष प्रदेश के 52 में से 39 जिलों में अतिवृष्टि और बाढ़ से बहुत अधिक क्षति हुई थी। राज्य में जून से सितंबर माह के बीच हुई वर्षा से लगभग 60 लाख 47 हजार हेक्टेयर क्षेत्र की 16 हजार 270 करोड़ की फसल प्रभावित हुई थी। इसमें लगभग 53 लाख 90 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में 33 प्रतिशत तक फसल क्षतिग्रस्त हुई थी। फसलों की कुल क्षति का अनुमान 16 हजार 270 करोड़ है। बांधों से गाद और रेत निकलने के बाद बाढ़ के मामले कम होंगे। सीडब्ल्यूसी के अनुसार, अगर गाद, रेत और बजरी को बांधों से निकाल दिया जाए तो उनकी उम्र बढ़ जाएगी। यानी मप्र सरकार ने बांधों से गाद और रेत निकालने का जो निर्णय लिया है, वह क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। मप्र के बांधों में रेत, गाद और बजरी इतनी मात्रा में भरी पड़ी है कि उम्रदराज बांधों पर खतरा मंडराने लगा है। प्रदेश के 25 बांध 100 साल से भी अधिक पुराने हो गए हैं और अधिकांश खतरे की जद में हैं। वैसे भी मप्र के बांध पिछले कुछ सालों से जर्जर अवस्था में पहुंच गए हैं। प्रदेश के करीब 91 बांध उम्रदराज हैं और ये कभी भी दरक सकते हैं।

इनका कहना है

मध्य प्रदेश में पहली बार जलाशयों से गाद (सिल्ट) और रेत निकाली जाएगी। गाद किसानों को दी जाएगी, जिसे वे खेतों में डालेंगे। इससे भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी। वहीं, इससे जो रेत प्राप्त होगी, उससे शासन को राजस्व मिलेगा। ठेका 15 से 25 साल के लिए उस कंपनी को दिया जाएगा, जिसका 3 साल का टर्नओवर 500 करोड़ रुपए होगा।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, प्रवक्ता, मप्र शासन

इन बांधों के निर्माण से लाभ कम नुकसान अधिक हुआ है, अब तक तो यही दर्शाता है। इन बांधों में गाद और रेत भरी पड़ी है। इससे बांधों पर दबाव बढ़ रहा है। राज्य सरकार गाद और रेत निकालने जा रही है, यह अच्छी बात है। इससे किसानों को भी अच्छा लाभा होगा। फसलों का उत्पादन भी बढ़ जाएगा। अन्य बांधों में भी यह प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए।

मेधा पाटकर, नबआं की नेत्री

मुरझाई फसलों को बारिश से मिली संजीवनी

प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने से आहत किसानों ने ली राहत की सांस

संवाददाता, भोपाल

प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने से सरकार ने राहत की सांस ली है। दरअसल, खरीफ फसलों की बोवनी होने के बाद बारिश नहीं होने से फसलें प्रभावित हो रही थीं। कई जगह बीज खराब हो गए तो फसलों की वृद्धि पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। शिवराज सरकार भी चिंता में थी। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिन क्षेत्रों में बोवनी रह गई है, वहां अब तेजी के साथ बोवनी होगी। धान का क्षेत्र भी बढ़ेगा, क्योंकि अगस्त के दूसरे सप्ताह तक इसकी बोवनी हो सकती है। प्रदेश में बारिश की स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होती जा रही है। करीब 15 दिन बारिश नहीं होने की वजह से बोवनी का सिलसिला थम गया था। इस बार 149 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बोवनी का लक्ष्य रखा गया है। अभी

प्रदेश में 72 फीसद से अधिक क्षेत्र में हो चुकी बोवनी, धान का बढ़ेगा रकबा

तक 72 फीसद बोवनी हो चुकी है।

खराब होने लगा था बीजः धान सहित अन्य फसलों को बोवनी के बाद बारिश नहीं होने से बीज खराब होने लगे थे। तापमान अधिक होने की वजह से फसलें भी मुरझा रही थीं और वृद्धि भी प्रभावित हो रही थी, लेकिन अब बारिश होने से स्थितियां तेजी के साथ बदल रही हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मानसून के रूठने से चिंता बढ़ गई थी।

बोवनी को लक्ष्य होगा पूराः अब उम्मीद है कि बोवनी का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। सोयाबीन की बोवनी जरूर इस बार लक्ष्य 61.64 लाख हेक्टेयर से कम रहेगी। अभी तक लगभग 45 लाख हेक्टेयर में ही बोवनी हुई है। मक्का की बोवनी 14.91 लाख हेक्टेयर में होनी थी जो लक्ष्य के करीब पहुंच चुकी है। जिन क्षेत्रों में धान की बोवनी नहीं हो पाएगी। वहां अब किसान मक्का लगाएंगे।

इनका कहना है

यदि एक सप्ताह और मानसून सक्रिय नहीं होता तो किसानों के साथ सरकार को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। किसान बोवनी नहीं कर पाते और जो फसल लग भी गई थी वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती, क्योंकि नमी नहीं होने से वृद्धि रुक गई थी। किसानों के पास अभी धान, मक्का सहित अन्य फसल लगाने के लिए समय है। मौसम के खुलते ही बोवनी का काम तेजी से प्रारंभ हो जाएगा।

डॉ. जीएस कौशल, पूर्व कृषि संचालक, मप्र

मध्यप्रदेश में 'देवारण्य' से समृद्ध होंगे आदिवासी

मुख्यमंत्री के सामने होगा योजना का प्रस्तुतिकरण

भोपाल। मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए राज्य सरकार देवारण्य योजना ला रही है। इसके तहत इस वर्ग के लोग औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती, भंडारण, प्रसंस्करण करेंगे और इन पर आधारित उद्योग भी लगा सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार मदद करेगी। आयुष विभाग की इस योजना को जल्द ही मंजूरी मिल सकती है। विभाग के अधिकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने योजना का प्रस्तुतीकरण देंगे। जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में रोजगार व आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार आयुष आधारित गतिविधियां बढ़ाने जा रही है। प्रस्तावित योजना के तहत औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती, उन पर आधारित उद्योग, दवा निर्माण, भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन, आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण और स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देना, स्व-सहायता समूहों को सशक्त करना, नर्सरी स्थापित करना आदि काम किए जाएंगे। यह योजना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के सहयोग से आयुष विभाग चलाएगा। इसमें मनरेगा तथा अन्य योजनाओं का सहयोग भी लिया जाएगा।

5 जिलों में शुरू होगी योजना

प्रयोग के तौर पर यह योजना प्रदेश के पांच जिलों सतना, झाबुआ, बैतूल, होशंगाबाद और डिंडोरी जिले में शुरू होगी। जिलों को योजना के तहत जरूरी तैयारियां करने को कह दिया गया है।

हर गांव, ब्लॉक और वार्ड स्तर पर प्रशासन ढूंढेगा कि कौन किस योजना का हकदार

हितग्राही को तलाशेगी योजना, क्योंकि 50 प्रतिशत आबादी को नीतियां पता नहीं

संवाददाता, भोपाल

अब तक आपने किसी योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही के चक्कर लगाने की बात ही सुनी होगी लेकिन अब ठीक उल्टा होने जा रहा है। दरअसल, अगले कुछ दिनों में प्रशासन के नुमाइंदे गली, मोहल्ले, वार्डों से ऐसे हितग्राहियों को ढूंढ़ निकालेंगे जिसे शासन की कोई न कोई योजना का फायदा पहुंचाया जा सके। इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि पात्र होने के बावजूद 50 फीसदी आबादी को यह पता ही नहीं कि वह किस-किस योजना का लाभ ले सकती है। सरकारी योजनाओं की बात की जाए तो सामान्य तौर पर दो, चार, छह स्कीम का नाम ही सामने आता है, जबकि केंद्र और प्रदेश की ओर से संचालित होने वाली लाभकारी योजनाओं की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। वजह यह है कि 50 फीसदी लोगों को पता ही नहीं होता है कि वे किस योजना का फायदा ले सकते हैं। जिला प्रशासन अब इस प्रक्रिया को बेहद आसान बनाने जा रही है।

हितग्राही का पूरा डाटा जुटाया जाएगा

इसी माह से शुरू होने वाले अभियान को सितंबर तक चलाया जाएगा। पता चला है कि प्रशासनिक अमला पहले वार्ड, ब्लॉक स्तर पर आमदनी, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के मामले में जानकारी एकत्रित करेगा। इसके बाद स्क्रीनिंग कर अलग-अलग योजनाएं तलाशी जाएंगी। संबंधित व्यक्ति तक पहुंचकर उसे पूरी जानकारी और पात्रता का लाभ दिलाने की जिम्मेदारी भी प्रशासनिक अधिकारियों की होगी।

पंचायत और वार्ड स्तर पर बैठक

पता चला है कि हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए वार्ड स्तर और पंचायत स्तर पर बैठकें भी आयोजित की जाएंगी और लोगों से उनकी समस्याएं भी पूछी जाएंगी। प्रशासन का दावा है कि अब जो लोग पात्र हैं उनसे संपर्क किया जाएगा। जिन्हें योजनाओं का लाभ लेना है उन्हें शामिल किया जाएगा और जिन्हें नहीं लेना वे अगर चाहें तो इससे अलग हो सकते हैं।

अधिकांश को योजनाओं का पता नहीं

दरअसल, प्रदेश में सरकार द्वारा लोगों के हित के लिए जो योजनाएं क्रियान्वित हैं उनकी जानकारी अधिकांश को नहीं है। इस कारण योजनाओं का फायदा पात्र लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में शासन-प्रशासन की कोशिश है कि हर व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। प्रशासन द्वारा हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अधिकारी और कर्मचारी हितग्राही से खुद ही संपर्क करेंगे, कई लोगों को अभी भी कई योजनाओं की जानकारी नहीं है जिससे वे लाभ से वंचित रह जाते हैं उन तक योजनाएं पहुंचाई जाएंगी। इसके लिए तीन माह का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है।

सरपंचों के प्रधान होते ही गांवों में मजदूरों से दूर हो गई मनरेगा

भोपाल। ग्राम पंचायतों में जनता द्वारा चुने गए पंच-सरपंच का कार्यकाल 2020 में पूरा हो चुका है। बीते डेढ़ से पंचायतों में समितियां गठित की गई हैं, जिनकी कमान निवर्तमान सरपंचों के ही हाथ, लेकिन अब यह सरपंच की बजाय पंचायत के प्रधान कहलाते हैं। सरपंच के नाम के साथ ग्राम पंचायतों में कामकाज के तौर-तरीके ऐसे बदले हैं, कि जॉबकार्ड धारी मजदूरों से मनरेगा योजना दूर हो गई है। मजदूरों की जगह जेसीबी, ट्रैक्टर-ट्रॉली आदि मशीनें काम कर रही हैं।

- ग्राम पंचायतों में जनता द्वारा चुने गए पंच-सरपंच का कार्यकाल 2020 में हो चुका पूरा
- बीते डेढ़ साल से पंचायतों में समितियां गठित की गई हैं, जिनकी कमान निवर्तमान सरपंचों के ही हाथ में है

मनरेगा का नियम है, कि स्वीकृत बजट का 60 फीसदी हिस्सा मजदूरों पर खर्च हो और 40 फीसदी बजट से निर्माण सामग्री (पत्थर, सीमेंट, रेत, सरिया, गिट्टी आदि) खरीदी जाए। जब पंचायतों में पंच-सरपंच थे तब काफी हद तक ऐसा ही हो रहा था, लेकिन अब हकीकत यह है, कि जॉबकार्डधारी मजदूरों तक 60 तो क्या 30 फीसदी बजट नहीं पहुंच पा रहा। इसका कारण यह है कि ग्राम पंचायतों के प्रधान (सरपंच) को अब जनपद या जिला पंचायत का खास डर रहा नहीं। क्योंकि उनकी नियुक्ति कलेक्टर ने की है। पहले जिपं सीईओ धारा 40 में वसूली और धारा 92 के तहत पद से पृथक कर सकते थे, अब जिला पंचायत सीईओ को यह अधिकार नहीं रहे, संभवत: यही कारण है कि सरपंच बने प्रधान बने कइयों जनप्रतिनिधि पंचायत की बजाय खुद का विकास करने में जुटे हैं।

पंचायतों में भ्रष्टाचार की शिकायतें चरम पर: हैरानी इस बात की है, कि पंचायतों में भ्रष्टाचार की शिकायतें बीते एक साल में चरम पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन मुरैना जिला प्रशासन, जिला पंचायत या जनपदें इस दौरान किसी एक भी पंचायत के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायत व उपयंत्री पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। इससे अधिकारियों की नीयत पर भी संदेह बढ़ना लाजिमी है।

किसानों को एप बताएगा आलू की खेती के लिए कैसी खाद डालना होगी

आलू की बेहतर फसल के लिए उर्वरक एप करेगा हेल्प

संवाददाता, भोपाल

आलू की बेहतर फसल के लिए केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र ग्वालियर ने शिमला स्थित मुख्यालय के साथ मिलकर एक एप तैयार किया है। इस एप में किसानों को अपने खेत की मिट्टी की रिपोर्ट दर्ज करना होगी। इससे एप बताएगा कि किसान आलू की खेती के लिए खेतों में कितनी और कैसी खाद डालें। आलू की खेती को बढ़ावा देने के लिए पहली बार सिर्फ आलू की खेती पर आधारित एप बनाया गया है। देश में पंजाब में आलू आधारित एप के बाद यह मप्र में दूसरा एप होगा।

ज्ञात रहे कि ग्वालियर स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र में आलू के प्रजनक बीजों को तैयार किया जाता है। इसमें अलग-अलग तरह की किस्में तैयार होती हैं। केंद्र से बाहर के राज्यों के किसान भी बीज लेते हैं और शासकीय सप्लाई भी होती है। आलू अनुसंधान केंद्र के द्वारा तैयार एप खाद के बेहतर मिश्रणों को बताएगा।

मप्र के लिए उर्वरक एप

केंद्रीय आलू अनुंसधान केंद्र और मुख्यालय शिमला की टीम ने प्रदेश के लिए जो एप तैयार किया है, उसका नाम मप्र के लिए उर्वरक एप रखा है। यह प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा। इसके बाद एप यह बताएगा कि उर्वरक का मिश्रण कितना-कितना और कैसे करना है।

एप से बढ़ेगी कार्ड की उपयोगिता

आलू वैज्ञानिकों के अनुसार देशभर में बड़े पैमाने पर साइल हेल्थ कार्ड बनाए गए, जिसका उपयोग ज्यादा किसान नहीं कर पा रहे थे। अब इस एप के तैयार होने के बाद साइल हेल्थ कार्ड का डाटा आसानी से किसान एप में दर्ज करके आलू की अच्छी खेती कर सकेंगे।

प्रदेश में इंदौर अग्रणी

प्रदेश में आलू की खेती में फिलहाल सबसे अग्रणी जिला इंदौर है। इसके बाद उज्जैन, देवास जैसे जिले हैं। वहीं ग्वालियर चंबल संभाग में मुरैना में आलू उत्पादन थोड़ा ठीक है। अब इस एप से प्रदेश के किसान आलू की खेती के लिए आगे बढ़ सकेंगे।

इनका कहना है

प्रदेश में आलू आधारित खेती के लिए पहली बार एप तैयार कराया जा रहा है। ग्वालियर और मुख्यालय की टीम ने मिलकर इसे तैयार किया है। इसे जल्द ही लांच किया जाएगा। अभी तक आलू की खेती के लिए एप पंजाब में है, यह ऐसा दूसरा एप होगा।

डॉ. एसपी सिंह, प्रमुख वैज्ञानिक, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, ग्वालियर

गवर्नर मंगू भाई पटेल ने महिला बाल विकास विभाग की बैठक में बनाई रणनीति

सरकार की योजनाओं की नब्ज टटोलने गांव जाएंगे राज्यपाल

संवाददाता, भोपाल

मध्य प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने प्रदेश सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत परखने की तैयारी कर ली है। वो अब प्रदेश के ग्रामीण इलाकों का दौरा करेंगे। हाल ही में उन्होंने राजभवन में महिला एवं बाल विकास विभाग की बैठक कर विभागीय योजनाओं की जानकारी ली। राज्यपाल ने कहा सरकारी योजनाओं की मंशा लोगों को फायदा पहुंचाने की होती है। योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए अफसरों को दौरा करना जरूरी है। राज्यपाल ने महिला बाल विकास विभाग के अफसरों को निर्देश दिए हैं कि वह ग्रामीण स्तर पर दौरा कर योजनाओं की सच्चाई को परखें। साथ ही जिन योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है उसके लिए भी लोगों से फीडबैक लें।

मैदान में जाएं कर्मचारी

राज्यपाल ने कहा स्थानीय स्तर पर काम के दौरान आने वाली समस्याओं और उनके समाधान के लिए विभागीय अफसरों का मैदानी कर्मचारियों से बातचीत करना जरूरी है। राज्यपाल ने कहा कुपोषण खत्म करने के लिए गर्भावस्था में ही महिला को पर्याप्त पोषण देने की जरूरत होती है। ऐसे में कुपोषण दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए कहा। राज्यपाल ने सरकार की योजनाओं का फायदा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करने की जरूरत बतायी। साथ ही कहा कि स्थानीय बोलियों में योजनाओं की जानकारी वो जनता को दें। सरकारी योजनाओं में समाज का सहयोग लेने के लिए कोशिश करें और योजनाओं का प्रचार करें।

कुपोषित बच्चों को पोषण आहार

राज्यपाल की बुलाई बैठक में अफसरों ने इस बात की जानकारी दी है कि प्रदेश में 32 हजार 172 आंगनबाड़ी केंद्रों में हितग्राही के घर और सरकारी स्थानों पर पोषण आहार वाटिका बनाकर पोषण मुहैया कराया जा रहा है। कुपोषित बच्चों और उनके परिवारों को 174 टन सामग्री फल सब्जी अनाज देकर पोषण देने की कोशिश हो रही है।

सरकार के काम पर पैनी नजर

राज्यपाल का पद संभालने के बाद से ही मंगू भाई पटेल लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। प्रदेश सरकार की योजनाओं पर राज्यपाल ने फीडबैक लेना शुरू किया है और इसकी शुरुआत महिला बाल विकास से की है। राज्यपाल आने वाले दिनों में दूसरे विभागों के अफसरों के साथ बैठक कर सरकार के कामकाज की समीक्षा करेंगे। मतलब साफ है कि अब प्रदेश सरकार के काम, योजनाओं और अमल पर राज्यपाल बारीकी से नजर रखेंगे।

अभी प्रदेश में 63 सामान्य और नौ उत्पादन वनमंडल

प्रदेश में 10 वनमंडल बंद करेगी सरकार

प्रमुख संवाददाता, भोपाल

राज्य सरकार प्रदेश में 10 वनमंडल बंद करने की तैयारी कर रही है। इनमें दो उत्पादन एवं अन्य सामान्य वनमंडल हैं। वन विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है। जल्द ही इस मामले में निर्णय होने की संभावना है। विभाग का तर्क है कि चयनित वनमंडलों में इतना काम नहीं बचा है कि वहां भारतीय वन सेवा के अधिकारी को पदस्थ किया जाए। इन वनमंडलों को समाप्त कर नजदीक के दूसरे वनमंडलों में मर्ज किया जाएगा। प्रदेश में 63 सामान्य और नौ उत्पादन वनमंडल हैं। इनमें से ऐसे 10 वनमंडल का चयन किया गया है, जिनमें घने जंगल हैं और वहां संरक्षण के अलावा अन्य कोई काम नहीं बचा है। मसलन, पौधारोपण या उत्पादन की दृष्टि से ये वनमंडल अंतिम पंक्ति में शामिल होते हैं।

वनमंडलों में नहीं बची भूमि

वन विकास निगम और संरक्षित क्षेत्रों के बफर जोन में जमीन जाने के कारण इन वनमंडलों में भूमि भी कम ही बची है। इन सब कारणों को देखते हुए इन्हें बंद करने का निर्णय लिया जा रहा है। इनमें रायसेन, देवास उत्पादन वनमंडल, पश्चिम वनमंडल मंडला, पश्चिम वनमंडल बैतूल, खंडवा का सेंधवा, शहडोल, छिंदवाड़ा, सिवनी सहित अन्य वनमंडल शामिल हैं।

निगम के अधिकार में गया क्षेत्र

वन अधिकारी बताते हैं कि मंडला, सिवनी और बैतूल ऐसे वनमंडल हैं, जिनका बड़ा हिस्सा वन विकास निगम के कार्यक्षेत्र में चला गया। वहीं कुछ हिस्सा नजदीक स्थित संरक्षित क्षेत्रों के बफर जोन के रूप में काम आ रहा है। छिंदवाड़ा में भी ऐसे ही हालात हैं। इसके बड़े हिस्से में वन विकास निगम की योजनाएं चल रही हैं। वहीं खंडवा का सेंधवा छोटा वनमंडल है। ऐसे में इन वनमंडलों में सामान्य या उत्पादन का कोई काम नहीं बचा है।

यह भी एक कारण

वनमंडल बंद करने के पीछे एक कारण यह भी है कि इनमें पौधारोपण सहित अन्य काम के लिए आने वाली राशि काफी कम होती है, इसलिए अधिकारियों का मन नहीं लगता। इनमें सबसे ज्यादा काम संरक्षण का ही है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर में घने जंगल हैं। जहां पौधारोपण किए जाने से ज्यादा पहले से उगे हुए वनों की सुरक्षा की जरूरत है। साथ ही घने जंगल होने के कारण शिकार की घटनाएं रोकना भी चुनौती है, इसलिए अधिकारी यहां पदस्थ होने से बचने की कोशिश करते हैं।

वनमंडलों का होगा विस्तार

इन वनमंडलों को खत्म कर सरकार इस क्षेत्र को आसपास के दो वनमंडल में बांट देगी। इससे उन वनमंडलों का क्षेत्र बढ़ जाएगा और फिर उन वनमंडल में मुख्य वनसंरक्षक स्तर के अधिकारी को भी पदस्थ किया जा सकता है। इसे लेकर भी अंदर ही अंदर विचार शुरू हो गया है।

किसानों को आत्मनिर्भर बनाने सरकार कर रही काम

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा

भोपाल/नई दिल्ली

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर तोमर ने कहा कि राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति पीएम-किसान योजना, किसान मानधन योजना, कृषि अवसंरचना कोष और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए परियोजना निगरानी इकाई के रूप में कार्य करेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने तथा कृषि कार्य संबंधी व्यय के लिए प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना लागू की है। इस योजना के तहत अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के खातों में 1.37 लाख करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की जा चुकी हैं। तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार देश के एक्सपर्ट्स, आईटी कंपनियों के साथ मिलकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नई प्रौद्योगिकी के साथ कार्यकर रही हैं।

यह भी हुए शामिल

कार्यक्रम में कृषि मंत्रालय के दोनों राज्य मंत्री कैलाश चौधरी व शोभा करंदलाजे, सचिव संजय अग्रवाल, पीएम- किसान स्कीम के सीईओ विवेक अग्रवाल तथा अन्य अधिकारी व कर्मचारी और विभिन्न एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए।

पौधा प्राधिकरण के माध्यम से हो रहा किसानों के अधिकारों का संरक्षण: इधर, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर ने पूसा, नई दिल्ली में पौधा प्राधिकरण भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर तोमर ने कहा कि पौधा प्राधिकरण के माध्यम से किसानों के अधिकारों का संरक्षण हो रहा है, जिसके लिए भारतीय संसद ने दुनिया के लिए यह एक अनूठा मॉडल दिया है। इससे किसान अपनी परंपरागत किस्मों के ऊपर और किसी अन्य किस्म के अपने ही पैदा किए हुए बीज के ऊपर अधिकार प्राप्त कर सकता है। साथ ही, यह भी सुविधा है कि बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन से किसानों का शोषण न हो। किसान पहले की तरह स्वतंत्रता से खेती कर सकते हैं व पौधा प्रजनक भी अपने पूरे अधिकार का संरक्षण कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि इस भवन के बनने से प्राधिकरण के न्यायालयों की स्थापना के लिए एक मंजिल व अन्य समर्थन प्रणालियों के साथ रजिस्ट्री कार्यके लिए दो मंजिलों की व्यवस्था रहेगी, जिससे आगंतुक किसानों व उपभोक्ताओं को आसानी होगी। आशा है कि नए कार्यालय भवन में अगले साल से काम होने लगेगा।

देश के इतिहास को दुरुस्त करने का अब सही अवसर

कृपाशंकर चौबे,
प्रोफेसर, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विवि, वर्धा

शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले इतिहास को दुरुस्त करने के लिए देशभर के शिक्षाविदों और विद्यार्थियों से सुझाव मांगे हैं। इतिहास को दुरुस्त करने की यह पहल तार्किक ही है, क्योंकि स्कूलों में अभी जो इतिहास पढ़ाया जाता है, वह एकांगी और पक्षपातपूर्ण है। यह पढ़ाया जाता है कि भारतीय राजाओं ने बड़ी लड़ाई लड़ी और हार गए, किंतु उन्होंने जो युद्ध जीते, उसका वृत्तांत नहीं दिया जाता है।

शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले इतिहास को दुरुस्त करने के लिए देशभर के शिक्षाविदों और विद्यार्थियों से सुझाव मांगे हैं। इतिहास को दुरुस्त करने की यह पहल तार्किक ही है, क्योंकि स्कूलों में अभी जो इतिहास पढ़ाया जाता है, वह एकांगी और पक्षपातपूर्ण है। यह पढ़ाया जाता है कि भारतीय राजाओं ने बड़ी लड़ाई लड़ी और हार गए, किंतु उन्होंने जो युद्ध जीते, उसका वृत्तांत नहीं दिया जाता है। उदाहरण के लिए आठवीं शताब्दी में 36 वर्षों तक युद्ध कर अपने राज्य का विस्तार करते रहे कश्मीर के कर्कोटक नागवंशी सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड के बारे में स्कूली इतिहास की किताबें खामोश हैं। उन्होंने अरब के मुसलमान आक्रांताओं तथा तिब्बती सेनाओं को पीछे धकेला था। उनका राज्य पूरब में बंगाल, दक्षिण में कोंकण, पश्चिम में तुर्किस्तान और उत्तर पूर्व में तिब्बत तक फैला था। ललितादित्य ने कश्मीर में मार्तंड मंदिर बनाया था। ग्यारहवीं शताब्दी में गजनवी सेनापति सैयद सालार मसूद गाजी को पराजित करने वाले श्रावस्ती के राजा सुहेलदेव के बारे में भी स्कूली इतिहास की किताबों में सुसंगत विवरण नहीं मिलता। इसी तरह 1741 में डचों को हराने वाले राजा मार्तंड वर्मा के बारे में इतिहास की किताबें प्रकाश नहीं डालतीं। चोल, चालुक्य, देवबर्मन, अहोम राजाओं के बारे में भी इतिहास की किताबें लगभग मौन हैं। दक्षिण भारत से लेकर ओडिशा, बंगाल और पूर्वोत्तर के अनेक प्रतापी राजाओं ने दो-ढाई सौ वर्षों तक शासन किया, पर उनके बारे में स्कूली इतिहास की किताबों में यथोचित विवरण नहीं मिलता। स्कूलों में भारत का जो इतिहास पढ़ाया जाता है, वह मुख्यत: दिल्ली का इतिहास है। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे समय इतिहास के एकांगी पक्ष को दूर करने का सुअवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। किसी भी देश का इतिहास कितना ही गौरवपूर्ण क्यों न हो, जब तक उसे सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जाता, तब तक वह प्रेरणादायी नहीं हो सकता। बहुत कम पुस्तकें हैं जिनसे प्रेरणाएं ली जा सकें। इस दृष्टि से काशीप्रसाद जायसवाल की किताब हिंदू राज्य तंत्र और गोविंद सखाराम सरदेसाई द्वारा 12 खंडों में लिखी गई भारत का इतिहास को मानक माना जा सकता है। हिंदू राज्य तंत्र पुस्तक दो खंडों में विभक्त है। पहले खंड में आरंभिक काल, महाभारत काल के राजनीतिक ग्रंथ, ईसा चौथी एवं पांचवीं शताब्दी के ग्रंथों, हिंदू धर्मशास्त्रकारों के चौदहवीं से अठारहवीं शताब्दी तक के ग्रंथों, छठी एवं सातवीं शताब्दी के ग्रंथों और आरंभिक मध्य युग के ग्रंथों, नीति एवं धर्म संबंधी ग्रंथों का विवेचन किया गया है। उसके बाद सभा-समितियों के कार्य का विवरण देते हुए हिंदू प्रजातंत्रों के आरंभ का इतिहास बताया गया है। बौद्ध संघ के प्रजातंत्र से लेकर हिंदू प्रजातंत्र का विवरण दिया गया है। मौर्य साम्राज्य, वैदिक काल, हिंदू एकराजत्व का विवरण भी विस्तार से दिया गया है। काशीप्रसाद जायसवाल ने भारतीय दृष्टि से इतिहास लिखा। वही काम गोविंद सखाराम सरदेसाई ने किया। उन्होंने 1000 से 1857 तक का भारत का इतिहास बारह खंडों में लिखकर मुसलमान, मराठा और अंग्रेजों के इतिहास का व्यापक, सही और सुसंगत विवरण दिया। इतिहास में केवल प्रामाणिक तथ्य दिए जाते हैं। पात्र, परिस्थितियां और घटनाएं इतिहास सम्मत होती हैं और इतिहास लिखने वाले के पास उन्हें प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सामग्री होती है, किंतु समस्या तब होती है जब किसी ऐतिहासिक घटना को लेकर इतिहासकारों में मतैक्य न हो। उदाहरण के लिए 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के बारे में इतिहासकारों के चार मत हैं। एक मत उन अंग्रेजपरस्त अध्येताओं का है कि 1857 की जनक्रांति गदर-विफल बगावत थी। दूसरा मत उन अध्येताओं का है कि वह जनक्रांति भारतीय सामंतों के स्वार्थ की लड़ाई थी। तीसरे मत में कुछ अध्येताओं ने उस क्रांति में आदिवासियों, दलितों एवं अन्य छोटी जातियों के अन्याय विरोधी संघर्ष की झलक देखी थी तो चौथे मत के इतिहासकारों की राय में 1857 का संग्राम

अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के उत्कट बलिदानों से भरा एक सुनियोजित महासंग्राम था। राष्ट्रीय चेतना जगाने और अंग्रेजी राज्य से मुक्ति का वह पहला संगठित आंदोलन देश की मर्यादा और आत्मसम्मान के लिए लड़ा गया था। तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं और संग्रहालयों में प्रमाणों सहित इतना साहित्य आज भी मौजूद है कि कोई देश या व्यक्ति चाहकर भी उससे किनारा नहीं कर सकता। चौथा मत इसलिए सर्वाधिक मान्य हुआ, क्योंकि वह इतिहास भारतीय दृष्टि से लिखा गया। इसके अलावा उन सभी गैर-राजनीतिक व्यक्तियों का इतिहास भी पढ़ाया जाना चाहिए, जिनका समाज पर असर रहा हो या जिनका राष्ट्र निर्माण में योगदान रहा हो। जैसे छह सौ साल हुए कबीर का जो प्रभाव समाज पर रहा है, उसे केवल साहित्य के विद्यार्थियों के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, इतिहास में भी शामिल करना चाहिए। उसी तरह इतिहास के विद्यार्थियों को शंकराचार्य के बारे में भी बताया जाना चाहिए कि किस तरह उन्होंने पूरब में गोवर्धन मठ, पश्चिम में शारदा मठ, उत्तर में ज्योतिर्मठ और दक्षिण में शृंगेरी मठ की स्थापना की। चारों दिशाओं में स्थापित होने वाले ये मठ भारत की एकता का परिचय देने वाले चिन्ह हैं। इसी तरह यह भी बताया जाना चाहिए कि किस तरह स्वामी विवेकानंद ने यूरोप और अमेरिका को वेदांत और योग से परिचित कराते हुए यह बोध कराया था कि वेदांत में सभी धर्मों की एकात्मकता व्यक्त होती है। इसी भांति इतिहास के विद्यार्थियों को यह भी पढ़ाया जाना चाहिए कि बीसवीं शताब्दी के पहले दशक में किस तरह सखाराम गणेश देउस्कर की किताब देशेर कथा का राष्ट्रीय जीवन में कितना व्यापक प्रभाव पड़ा।

पीएम नहीं करा सके नए मंत्रियों का परिचय

विपक्ष के लिए यह तय करना आवश्यक है कि वह अपने मसलों पर संसद में चर्चा करना चाहता या फिर हंगामा? यदि हंगामा होगा तो संसद में सरकार के जरूरी कामों में अड़ंगा लगेगा और ऐसा होने का मतलब है देश का नुकसान किया जाना। क्या विपक्ष यही चाहता है? जैसी आशंका थी, वैसा ही हुआ। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हंगामे से हुई और हंगामा भी ऐसा कि दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इसका अंदेशा पहले से था कि विपक्ष हंगामा करेगा, लेकिन यह आभास नहीं था कि वह प्रधानमंत्री को अपने नए मंत्रियों का परिचय कराने का भी अवसर नहीं देगा। विपक्ष की ओर से उठाए गए मुद्दों की महत्ता से इंकार नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री को अपने मंत्रियों को सदन से परिचित कराने का अवसर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि यह एक परंपरा है और संसद को अपनी परंपराओं के पालन के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। यदि इस परंपरा के निर्वहन के बाद विपक्ष अपनी बात कहता तो कोई देर या अंधेर होने वाली नहीं थी। विपक्ष ने हंगामा करने के लिए महंगाई, किसान आंदोलन आदि के अलावा जासूसी प्रकरण का भी सहारा लिया। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि यह मसला खासतौर पर विपक्ष को हंगामा करने के लिए उपलब्ध कराया गया। इसकी सुगबुगाहट जारी थी कि संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही मीडिया के एक हिस्से में ऐसा कुछ आएगा, जिससे विपक्ष को हंगामा करने में आसानी होगी। अंतत: ऐसा ही हुआ। इस आशय की खबरें आईं कि एनएसओ नामक एक इजरायली कंपनी के पेगासस स्पाईवेयर के जरिये कुछ चुनिंदा लोगों की जासूसी की कोशिश की गई। हालांकि खबरें यही कहती हैं कि पेगासस के जरिये जासूसी करने की कोशिश की गई और यह स्पष्ट नहीं कि इसमें सफलता मिली या नहीं, लेकिन विपक्ष अपनी सुविधा के लिए इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि चुनिंदा लोगों के मोबाइल फोन की जानकारी हासिल की गई अथवा उनकी बातें गोपनीय रूप से सुनी गईं। बेहतर हो कि इस मामले को उछालने वाले पहले इस बारे में सुनिश्चित हो लें कि जासूसी की गई या नहीं? इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सरकार के साथ संबंधित इजरायली कंपनी ने भी इससे इंकार किया है कि पेगासस के जरिये भारत समेत अन्य देशों के खास लोगों की जासूसी की गई। यह मामला कुछ इसी रूप में पहले भी सामने आ चुका है और तब भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका था। कहीं इस मामले को सिर्फ सनसनी पैदा करने के लिए ही तो नए सिरे से नहीं उछाला गया? वस्तुस्थिति जो भी हो, विपक्ष के लिए यह तय करना आवश्यक है कि वह अपने मसलों पर संसद में चर्चा करना चाहता है या फिर हंगामा? नि: संदेह यदि हंगामा होगा तो संसद में सरकार के जरूरी कामों में अड़ंगा लगेगा और ऐसा होने का मतलब है देश का जानबूझकर नुकसान किया जाना। क्या विपक्ष यही चाहता है?

देश में बढ़ती जनसंख्या से मुंह मोड़ने की कोशिश

संजय गुप्त

उत्तर प्रदेश विधि आयोग की ओर से जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा तैयार किए जाने के बाद बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनसंख्या नीति भी जारी कर दी। इसी के साथ जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जारी बहस और तेज हो गई।

उत्तर प्रदेश विधि आयोग की ओर से जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा तैयार किए जाने के बाद बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनसंख्या नीति भी जारी कर दी। इसी के साथ जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जारी बहस और तेज हो गई। इसका एक कारण उत्तर प्रदेश की तरह असम सरकार की ओर से भी जनसंख्या नियंत्रण के उपाय करना है। कुछ नेता और बुद्धिजीवी उत्तर प्रदेश सरकार की जनसंख्या नियंत्रण की पहल को न केवल आगामी चुनावों से जोड़ रहे हैं, बल्कि यह भी कह रहे हैं कि इसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय को निशाने पर लेना है। ऐसे लोगों का यह भी मानना है कि इस पहल के सार्थक नतीजे सामने नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसे प्रयास पहले भी विफल हो चुके हैं। इन लोगों का तर्क है कि जनसंख्या वृद्धि की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए करीब दो-तीन दशक बाद देश की आबादी बढ़ने की दर स्थिर हो जाएगी। ये लोग एक तो इसकी अनदेखी कर रहे हैं कि अगले दो-तीन दशक तो जनसंख्या बढ़ती ही रहेगी और दूसरे, योगी सरकार की जनसंख्या नीति में कहीं भी यह संकेत तक नहीं किया गया कि उसका उद्देश्य किसी समुदाय विशेष की आबादी पर रोक लगाना है। वैसे जनसंख्या नियंत्रण की पहल को मुस्लिम समुदाय से जोड़ना एक तरह से इसकी स्वीकारोक्ति है कि इस समुदाय में अन्य समुदायों की अपेक्षा आबादी तेजी से बढ़ रही है। पता नहीं, जनसंख्या नियंत्रण की पहल का विरोध कर रहे लोग यह क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि जब अन्य समुदायों ने छोटे परिवार की महत्ता को समझ लिया है तब फिर उसे शेष समुदाय भी समझें तो इसमें बुराई क्या है? यदि शेष समुदाय भी छोटे परिवार की महत्ता समझ लेते हैं तो इससे उनका ही हित होगा। आखिर इस सत्य से मुंह मोड़ने का क्या मतलब कि देश के कई हिस्सों में मुस्लिम समुदाय की आबादी वृद्धि दर अधिक है? इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि मुस्लिम समाज के बीच ऐसे लोग सक्रिय हैं, जो यह प्रचार करते हैं कि अधिक बच्चे पैदा करने में ही उनकी भलाई है या फिर बच्चे तो अल्लाह की मर्जी से पैदा होते हैं। मुसलमानों के बीच यह भी प्रचार किया जाता है कि अपनी अहमियत बनाए रखने के लिए आबादी तेजी से बढ़ाएं। आज भारत लगभग 1.4 अरब आबादी के साथ विश्व का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। अगले कुछ वर्षों में हम आबादी के मामले में चीन से भी आगे निकल जाएंगे। यह कोई उपलब्धि नहीं होगी। कुछ समय पहले तक हमारे समाजशास्त्री और राजनीतिज्ञ युवा आबादी को एक संपदा के तौर पर देखने के साथ यह मानकर चल रहे थे कि हम दूसरे देशों को मानव संसाधन उपलब्ध कराने में सफल रहेंगे, लेकिन तब शायद किसी ने इसकी कल्पना नहीं की थी कि इंटरनेट आधारित तकनीक बहुत कुछ बदल देगी। बीते कुछ समय से आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और रोबोटीकरण का चलन जिस तेजी से बढ़ा है, उससे रोजगार के मौके कम होते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में लोगों का काम मशीनें अधिक करेंगी। ऐसे में रोजगार का संकट और गहन होगा। आज चीन तेजी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और रोबोटिक्स को अपनाकर अपने कारखानों की उत्पादकता को एक नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। यह स्थिति कई विकसित देशों की भी है। जहां इन देशों के कारखाने कर्मचारी रहित होते जा रहे हैं, वहीं भारत आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल में बहुत पीछे है। कोविड काल में ऑफिस का काम घर से करने की जो सुविधा मिली, उसे अब स्थाई माना जा रहा है। तकनीक के इस्तेमाल के चलते आवाजाही कम होती जाएगी। इसका असर भी रोजगार के अवसरों पर पड़ेगा। एक तर्क यह दिया जाता है कि जरूरी नहीं कि भारत हर बात को अपनाए, पर पिछले दिनों भारत ने ड्रोन के जरिये माल डिलीवरी की संभावनाएं टटोलीं। अगर यह प्रयोग सफल रहता है तो तमाम डिलीवरी ब्वॉय की नौकरियां जा सकती हैं। तकनीक इसी तरह अन्य क्षेत्रों की नौकरियों को भी कम करने का काम करेगी। आज विकसित देशों में जिस काम को दो-तीन लोग करते हैं, उसे भारत में आम तौर पर सात-आठ लोग करते हैं। उत्पादकता के इस कमजोर स्तर का खामियाजा देश को भोगना पड़ रहा है। हम विश्व के उत्पादकता सूचकांक में कहीं पीछे हैं। हमारी एक बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन इस क्षेत्र की हमारी उत्पादकता कई दक्षिण एशियाई देशों से भी कम है। एक तर्क यह भी है कि जब लोग शिक्षित होंगे तो स्वत: ही छोटे परिवार की महत्ता समझ जाएंगे, लेकिन शिक्षा का खराब स्तर किसी से छिपा नहीं।

परेशान किसान अब हरी खाद की ओर अपना रुख कर रहे

बालाघाट में रासायनिक उर्वरक का विकल्प बनी हरी खाद

संवाददाता, बालाघाट

हरी खाद, जैविक कृषि की दिशा में कदम बढ़ा रहे किसानों के लिए रासायनिक खाद का विकल्प बन रही है। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व की मिट्टी में उर्वरक क्षमता बढ़ा रहे हैं, जिससे सन और ढेंचा से तैयार होने वाली हरी खाद फसलों के लिए संजीवनी साबित हो रही है। रासायनिक खाद का विकल्प अपनाने के लिए किसान अब फसलों के साथ हरी खाद का रकबा भी बढ़ा रहे हैं। जिले में किसान जैविक कृषि की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, परंपरागत कृषि अपनाने के लिए रासायनिक खाद का विकल्प तैयार कर रहे हैं। कृषि का अंदाज बदल रहे किसान खेतों में हरी खाद तैयार कर रहे हैं। इसके लिए किसान धान रोपने से पहले सन व ढेंचा की खेती कर रहे हैं। सन से हरी खाद तैयार करने के लिए कनई का एक किसान 20 एकड़ में सन की फसल तैयार कर रहा है। जैविक कृषि कर रहे ताराचंद बेलजी बतातें है कि किसान इससे जहां रासायनिक खाद का विकल्प पैदा कर रहे हैं। वहीं बीज तैयार कर इसे मुनाफे का विकल्प भी बना रहे हैं। जिले में पांच साल में हरी खाद बनाने किसानों के आगे आने से इसका रकबा तेजी से बढ़ रहा है। बालाघाट में 40 किसानों 200 एकड़ में हरी खाद बनाने सन का बीज बोकर इसका रकबा बढ़ाया है, इससे भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ रही है और जैविक कृषि भी। जिले में इस साल 40 किसानों ने उनसे प्रभावित होकर इसका बीज बोया है। इसकी खाद और बीज भी लाभ दे रहे हैं।

ऐसे जानें सन की खेती

हरी खाद बनाने के लिए फसल लगाने से एक, सवा माह पूर्व सन का बीज बोया जाता है। इसका पौधा तेजी से बढ़ता है, जो करीब तीन फीट तक हो जाता है। फसल लगाने से पूर्व इसे रोटरवेटर से खेत में मचा दिया जाता है। खेत में पानी भरकर इसे मिट्टी में दबा दिया जाता है। करीब तीन से चार दिन में इसके कीचड़ में फसल लगाई जा सकती है। सन से बनी खाद से खेत में डीएपी,यूरिया,पोटाश और गोबर खाद की जरूरत नहीं पड़ती है। यह इन सभी खादों का विकल्प है।

एक एकड़ में हरी खाद की क्षमता

- एक एकड़ में तैयार सन की खाद पांच ट्राली गोबर के बराबर
- 130 किलो सन की खाद डेढ़ क्विंटल यूरिया के समान
- डेढ़ क्विंटल सिंगल सुपर फॉस्फेट के बराबर
- 30 किलो पोटाश के बराबर

इनका कहना है

बाजार में अमानक खाद मिलने से फसलों के बिगड़ने और मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होने से किसान परंपरागत जैविक कृषि की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। इसके सुखद परिणाम भी सामने आ रहे हैं। फसलों की सेहत संवारने के साथ किसान समृद्धि भी बढ़ा रहे हैं। रासायनिक खाद का विकल्प तैयार करने हरी खाद बनाने के लिए सन और ढेंचा की खेती की जा रही है। जिससे फसल भी अच्छी पैदा हो रही है और इसके बीज तैयार करने से भी किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं।

डॉ. उत्तम बिसेन, कृषि वैज्ञानिक
राजा भोज कृषि कॉलेज

अमरूद इंडस्ट्रीज बनेगी सीहोर की नई पहचान

» पीएमएफएमई योजना में 60 आवेदन » छह किसानों के केस बैंक पहुंचाए

संवाददाता, सीहोर

चमकदार और सुनहरे शरबती गेहूं ने कृषि क्षेत्र में जिले को एक विशेष पहचान दी है। लेकिन अब यहां के बगीचों के खटटे-मिठी अमरूद और उससे बने उत्पाद बड़े बाजरों में पहुंचेंगे। निवेश के साथ ही युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। फूड प्रोसेसिंग को बढ़ाना देने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खादय प्रसंस्करण योजना शुरू की गई थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते बीते साल जिले को लक्ष्य नहीं मिले। कोरोना की रफ्तार थमने के बाद कृषि उद्यमियों के लिए विभाग ने पोर्टल ओपन कर दिया है और जिले के किसान इसमें रुचि दिखा रहे हैं। जिले में बड़ी मात्रा में अमरूद का उत्पादन होता है, इसलिए योजना के तहत अमरूद का चयन हुआ है। अमरूद उद्योग लगाने के लिए अभी तक उद्यानिकी विभाग में करीब 50 आवेदन आ चुके हैं जिनमें से 6 किसानों के प्रकरण बैंकों को पहुंचाए जा चुके हैं। गौरतलब है कि फूड प्रोसेसिंग और कृषि इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएमएफएमई योजना शुरू की गई है। इससे जिले में अमरुद का बगीचा रखने वाले किसानों को 30 लाख से 2 करोड तक ऋण उपलब्ध होगा। कच्चे की प्रोसेसिंग, मशीनरी, पैकेजिंग और बडे बाजारों तक माल पहुंचाने के लिए किसानों को लोन दिया जाएगा।

मिलते हैं अच्छे दाम

जिले में अच्छी और उन्नत किस्म का अमरुद बड़ी मात्रा में पैदा होता है। सीहोर, नसरुल्लागंज और बुधनी क्षेत्र से अमरुद बाहर की मंडियों में जाता है। इंदौर,भोपाल, देवास, होशंगाबाद की मंडियों में सीहोर के अमरुद को पसंद किया जा रहा है। इलाहबादी सफेदा, लखनबी 27, धारीवाला, चिठठीदार जैसे किस्मों के अच्छे दाम मिलते हैं।

इनका कहना है

योजना में बैंक लोने के लिए गारंटर की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा 10 लाख तक का अनुदान और बैंक ऋण पर 3 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। जिले में वर्तमान में अमरूद का कुल रकबा 1876, उत्पादन 6032 मीट्रिक टन है। अब किसान का उत्पाद बडे बाजारों तक पहुंचेगा और जिले में युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।

राजकुमार सागर, जिला उद्यानिकी अधिकारी, सीहोर

मुरैना में अब भदावरी नस्ल की भैंस होंगी तैयार

» यह नस्ल अधिक घी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध
» कृषि वैज्ञानिकों ने संरक्षण पर किया मंथन

मुरैना। भारतीय झांसी से आए वैज्ञानिकों के दल ने कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. एसपी सिंह के साथ मुरैना जिले में भदावरी संरक्षण कार्यक्रम पर विस्तृत परिचर्चा की गई। जिससे मुरैना जिले में भदावरी नस्ल की भैंस को बढ़ावा दिया जा सके। भदावरी भैंस मूल रूप से इटावा भिंड, आगरा और मुरैना जिले में पाई जाती हैं। यह नस्ल अधिक घी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार, हरियाणा के तत्वाधान में संचालित भैंस सुधार नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में भदावरी भैंस संरक्षण एवं सुधार परियोजना का संचालन किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत भदावरी नस्ल के चुनिंदा उत्तम सांड़ों से हिमीकृत वीर्य का उत्पादन किया जाता है। साथ ही इसे भदवारी प्रजनन क्षेत्र में कृत्रिम गर्भाधान के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

झांसी का दल आया मुरैना: अभी हाल ही में मुरैना जिले में झांसी से आए हुए वैज्ञानिक डॉ. बीपी कुशवाहा एवं डॉ. दीपक उपाध्याय द्वारा भदावरी नस्ल के हिमीकृत वीर्य की आपूर्ति की गई। कार्यक्रम में पशु चिकित्साधिकारी डॉ. ब्रजमोहन शर्मा, डॉ. दिनेश यादव, डॉ. अंकित यादव एवं पशु चिकित्सालय में पदस्थ अन्य स्टाफ उपस्थित रहा।

सरकार ने की डेयरी इन्वेस्टमेंट ऐक्सेलरेटर की स्थापना

डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अनोखी पहल

संवाददाता, भोपाल/नई दिल्ली

भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है जिसका वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 23 फीसदी का योगदान है। पिछले 5 वर्षों में देश के वार्षिक दुग्ध उत्पादन में 6.4 फीसदी (सीएजीआर) की बढ़ोतरी हुई है। अपने सामाजिक-आर्थिक महत्व के कारण डेयरी, भारत सरकार के लिए एक उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। यह देश की अर्थव्यवस्था में 5 फीसदी का योगदान करने वाला एकमात्र सबसे बड़ा कृषि उत्पाद है और 80 करोड़ से ज्यादा किसानों को सीधे रोजगार प्रदान करता है। इसके अलावा, देश में पैकेज्ड डेयरी उत्पाद का बहुत बड़ा घरेलू बाजार है, जिनकी कीमत 2.7 से लेकर 3.0 लाख करोड़ रुपए है। डेयरी क्षेत्र की उपयोगिता को देखते हुए सरकार ने डेयरी इन्वेस्टमेंट ऐक्सेलरेटर की स्थापना की है।

डेयरी इन्वेस्टमेंट ऐक्सेलरेटर की स्थापना

केंद्र सरकार ने डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और उसे सुगम बनाने को ध्यान में रखते हुए,अपने निवेश सुविधा प्रकोष्ठ के अंतर्गत डेयरी इन्वेस्टमेंट ऐक्सेलरेटर की स्थापना की है। यह इन्वेस्टमेंट ऐक्सेलरेटर निवेशकों के साथ इंटरफेस के रूप में काम करने के लिए गठित की गई एक क्रॉस फंक्शनल टीम है, जो निवेश चक्र में सहायता प्रदान करेगी।

उद्यमियों, निजी कंपनियों को मिलेंगे यह लाभ

डेयरी इन्वेस्टमेंट ऐक्सेलरेटर द्वारा निवेशकों के बीच पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (एएचआईडीएफ) के बारे में जागरूकता फैलाने का भी काम किया जाता है। एएचआईडीएफ, भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग की प्रमुख योजनाओं में से एक है जिसके अंतर्गत उद्यमियों, निजी कंपनियों, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और संभाग आठ कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया गया है। पात्र संस्थाओं द्वारा इस योजना का लाभ डेयरी प्रसंस्करण एवं संबंधित मूल्य संवर्धन बुनियादी अवसंरचना, मांस प्रसंस्करण एवं संबंधित मूल्य संवर्धन बुनियादी अवसंरचना और पशु आहार संयंत्र के क्षेत्रों में नई इकाइयों की स्थापना करने अथवा मौजूदा इकाइयों का विस्तार करने के लिए उठाया जा सकता है।

ऋण पर 3 फीसदी ब्याज की छूट

छह वर्ष अदायगी अवधि के साथ 2 वर्ष अवधि की छूट रहेगी। 750 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी भी मिलेगी। डीएएचडी द्वारा उन सभी निजी कंपनियों, विशिष्ट उद्यमियों और स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित किया जाता है। डेयरी क्षेत्र में निवेश करने और इन्वेस्टमेंट ऐक्सेलरेटर तक पहुंच प्राप्त करने में दिलचस्पी दिखाते हैं। वो संबंधित विभाग या उसकी वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पंजीयन 31 जुलाई तक

भोपाल। प्राकृतिक कारणों से फसलों को हुए नुकसानी की भरपाई लिए चलाई जा रही देशव्यापी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इस वर्ष भी खरीफ फसल का बीमा किया जा रहा है। यह योजना देश भर में एक समान रूप से लागू है। योजना के तहत किसानों को बीमा राशि का दो प्रतिशत की प्रीमियम जमा कर के बीमा करवा सकते हैं। देश के अलग-अलग राज्यों तथा जिलों के अनुसार अलग-अलग फसलों की बीमा राशि अलग-अलग अधिसूचित की जाती है। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी कई खरीफ फसलों के लिए राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक है। इसके बाद किसी भी ऋणी या अऋणी किसानों का फसल बीमा नहीं किया जाएगा।

पीएम फसल बीमा योजना कब तक किया जाएगा

देश के जितने भी राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू है, उन सभी राज्यों के इच्छुक किसान 31 जुलाई तक अपनी क्षेत्र के फसल के अनुसार बीमा करा सकते हैं। इस योजना के तहत ऋणी तथा अऋणी दोनों प्रकार के किसान जुड़ सकते हैं। अधिसूचित फसल को बीमित कराने हेतु इच्छुक कृषक फसल बीमा के लिए 31 जुलाई तक नजदीकी बैंक, वित्तीय संस्था, लोक सेवा केन्द्रों, बीमा कंपनी में संपर्क कर फसल बीमा करा सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में अधिक

जानकारी के लिए कृषि कार्यालय, बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 31 जुलाई तक किया जा रहा है। इसके बाद बैंक फसल के अनुसार प्रीमियम काटकर कंपनी को भेज दी जाएगी। इसके लिए 15 अगस्त लास्ट डेट हैं। 15 अगस्त के बाद किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वेबसाईट पर जाकर चेक कर सकते हैं।

देय प्रीमियम: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रीमियम में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। पहले की तरह ही खरीफ सीजन के फसल के लिए 2 प्रतिशत, रबी सीजन के फसल के लिए 1.5 प्रतिशत तथा मौसम आधारित फसल बीमा के लिए 5 प्रतिशत का प्रीमियम रखा गया है। नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किसानों को आधार संख्या, बैंक पासबुक, भूमि रिकॉर्ड / किरायेदारी समझौते, और स्व-घोषणा प्रमाण पत्र ले जाना होगा।

25 लाख के लोन और 10 लाख रुपए की सब्सिडी लेकर कस्टम प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के लिए करें आवेदन

भोपाल। कृषि आधारित उद्योग लगाने एवं ग्राम स्तर पर रोजगार सृजित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत कई योजनाओं की शुरुआत की गई है, जिसमें योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों आदि की स्थापना पर इच्छुक लाभार्थियों को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाना एवं लाभार्थियों को अनुदान देना शामिल है। मप्र सरकार ने इसके तहत देश की पहली कस्टम प्रोसेसिंग यूनिट योजना शुरू की है। इस योजना के तहत गांव के युवा कृषि संबंधित उद्योग लगाकर रोजगार सृजित कर सकते हैं। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के कोई भी युवा इस योजना के लिए आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 40 प्रतिशत की सब्सिडी पर राज्य के निवासी प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं। यह प्रोसेसिंग यूनिट दलहन, तेलहन, ग्रेडिंग, सफाई तथा अन्य प्रकार के कार्य करने वाली मशीनों पर दी जाएगी। यह सभी मशीनों पर आवेदक को 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी के लोन एवं ब्याज में छूट आदि सुविधाएं भी दी जा रही हैं।

मशीने इस प्रकार है

- मिनी राईस मिल
- मिनी दाल मिल
- आईल एक्सट्रेक्टर
- मिलेट प्रसंस्करण प्लांट
- मल्टी कमोडिटी फ्लोर मिल / दलिया मिल
- सीड प्रोसेसिंग प्लांट
- सहायक मशीनरी जैसे पेकिंग और सीलिंग यूनिट

क्या है कस्टम प्रोसेसिंग यूनिट: किसानों को कृषि फसलों के प्राथमिक प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) के लिए मशीने उपलब्ध कराकर सेवाएं देने के उद्देश्य से बैंक ऋण आधार पर कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित करने के इच्छुक आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने के लिए व्यक्ति, पंजीकृत किसान समूह तथा फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन पात्र होंगे। ये कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र राज्य के प्रत्येक जिले में खोले जाना है। प्रत्येक कस्टम प्रोसेसिंग मशीनों की खरीद पर आवेदकों को लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रुपए का क्रेडिट लिंक्ड एंडेड अनुदान दिया जाएगा। अनुदान की गणना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाइजेशन योजना के तहत की जाएगी। इसके साथ ही हितग्राही भारत सरकार के एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत लाभ प्राप्त कर अतिरिक्त तीन प्रतिशत की ब्याज पर सब्सिडी ले सकेंगे।

इन मशीनों की खरीद पर सब्सिडी: कस्टम प्रोसेसिंग यूनिट के तहत विभिन्न प्रकार के मशीन किसान अनुदान पर ले सकते हैं। जिससे छोटे स्तर पर उद्योग शुरू किया जाए। एक इकाई में क्लीनिंग-ग्रेडिंग प्लांट आवश्यक रूप से रखा जाना होगा जिसमें डी-स्टोनर, ग्रेविटी सेप्रटर तथा ग्रेडीएंट सेप्रटर सम्मिलित होना आवश्यक है। क्लीनिंग-ग्रेडिंग प्लांट की न्यूनतम क्षमता 500 किलोग्राम प्रति घंटा होना आवश्यक है। इसके अतिरक्त फसलों की प्रोसेसिंग से सम्बंधित अन्य मशीनों को रखा जा सकेगा जिसका चयन नीचे दी गई मशीनों से किया जा सकता है। क्लीनिंग-ग्रेडिंग प्लांट एवं अन्य प्रसंस्करण मशीनों को भारत सरकार आईसीएआर द्वारा निर्धारित मापदंडों की पूर्ति करना आवश्यक होगा।

यूनिट लगाने का लक्ष्य: इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने मध्यप्रदेश के प्रत्येक जिले के लिए 5 प्रोसेसिंग यूनिट का लक्ष्य रखा है। राज्य में कुल 260 कस्टम प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएंगी। इसके तहत सामान्य वर्ग के लिए 200 यूनिट तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 30-30 यूनिट का लक्ष्य है। सभी जिलों एवं सभी वर्गों के किसान इस योजना के तहत आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

कस्टम प्रोसेसिंग यूनिट के तहत अनुदान: राज्य सरकार ने कस्टम प्रोसेसिंग यूनिट योजना कि कुल लागत 25 लाख रुपए रखी है। इस योजना के तहत कस्टम प्रोसेसिंग केंद्र स्थापित करने के लिए किसानों को 40 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा इस योजना पर तीन प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा।

बैंक ड्राफ्ट कितने का रहेगा: कस्टम प्रोसेसिंग यूनिट के लिए किसान को सहायक कृषि यंत्री के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनाना होगा। संन्य वर्ग के आवेदक के लिए 10,000 तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 5,000 रुपए की बैंक ड्राफ्ट सहायक कृषि यंत्री के नाम बनाकर जमा करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के साथ धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट की स्केन प्रति अपलोड की जाना होगी। बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति अभिलेखों के सत्यापन के समय संबंधित कार्यालय में जमा करायी जानी अनिवार्य होगी।

आवेदक बैंक ड्राफ्ट कब जमा करना होगा: चार अगस्त तक आवेदन के बाद किसानों को अभिलेखों को सत्यापन तथा बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा। आवेदक अभिलेखों का सत्यापन एवं बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए 10 अगस्त से 13 अगस्त तक सुबह 10:30 से सायं 5:30 तक करा सकते हैं। आवेदक अभिलेखों में निम्नलिखित दस्तावेज होना जरुरी है। आवेदक के पास फेटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, सक्षम धिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाईस्कूल अंकसूची, जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आवेदकों के लिए) निवास प्रमाण पत्र (मतदाता परिचय पत्र अथवा आधार कार्ड) अथवा ऋण पुस्तिका, 12 वीं उत्तीर्ण अंकसूची सत्यापन के लिए प्रस्तुत किए जाने होंगे।

आवेदन कब करना है: वित्त वर्ष के लिए मप्र के सभी किसान कस्टम प्रोसेसिंग यूनिट के लिए 4 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिलों के आवेदक कस्टम हायरिंग के लिए अभिलेखों का सत्यापन तथा बैंक ड्राफ्ट जमा करने के लिए 6 केंद्र बनाए गए हैं।

भोपाल में सीएनजी से भरेगा नगर निगम का खजाना

» डेढ़ साल में होगा तैयारः बाजार भाव से पांच रुपए सस्ती बिकेगी

» आदमपुर खंती में होगा प्लांट, निगम हर साल मिलेगी 61 लाख रायल्टी

संवाददाता, भोपाल

गीले कचरे से बायो सीएनजी गैस बनाने के लिए आदमपुर छावनी खंती क्षेत्र में सीएनजी प्लांट लगाने के लिए काम शुरू हो गया है। यहां बाउंड्रीवाल का काम चल रहा है। वहीं, 200 टन गीले कचरे से यहां 6400 केजी सीएनजी गैस का उत्पादन होगी। इससे सालाना दो करोड़ 43 लाख की बचत भी होगी। लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से इस प्लांट का निर्माण करवाया जा रहा है। जिसमें वर्तमान कचरे को प्रोसेस कर कंपनी द्वारा 50 फीसद गैस नगर निगम भोपाल को दी जाएगी। साथ ही 50 फीसद गैस बाजार भाव से पांच रुपए कम कीमत पर मार्केट में बेची जाएगी। इससे होने वाले फायदे से ही नगर निगम को रायल्टी दी जाएगी। इधर, भोपाल नगर निगम को मिलने वाली गैस से बीसीएलएल की बसों का संचालन होगा। आगामी डेढ़ साल में यह प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद नगर निगम को हर साल 61 लाख रुपए का लाभ होगा। वहीं नगर निगम के अपर आयुक्त एमपी सिंह का कहना है कि काम शुरू हो गया है। डेढ़ साल में प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। इससे नगर निगम भोपाल और आम जनता को भी फायदा होगा। बाजार मूल्य से पांच रुपये कम दाम पर सीएनजी गैस उपलब्ध कराई जाएगी।

पेट्रोल 111 रुपए लीटर

दरअसल, भोपाल में पेट्रोल के दाम 111 रुपए से ऊपर पहुंच चुके हैं। पेट्रोल के बढ़ते दाम के चलते लोग अब इसका विकल्प तलाशने में लगे हुए है। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल और सीएनजी से चलने वाले वाहनों की तलाश अब शहर में युवा पीढ़ी कर रही है। इसके चलते राजधानी में भी सीएनजी के सात प्लांट लगाए जा रहे हैं। इसमें से आदमपुर और बैरागढ़ में दो प्लांट लगाने का काम शुरू हो गया है।

45 रुपए किलो मिल रही सीएनजी

राजधानी में सीएनजी गैस के वर्तमान में दाम 45 रुपए केजी है। इस प्लांट के यहां खुल जाने के बाद लोगों को सस्ता ईंधन उपलब्ध हो पाएगा। वहीं पेट्रोल से निकलने वाले धुएं से पर्यावरण को होने वाला नुकसान भी नहीं होगा। इतना ही नहीं कचरे से सीएनजी बनने के बाद कचरा कंपोस्ट खाद के रूप में बाहर निकलेगा।

एक नजर में प्रोजेक्ट

- » प्रोजेक्ट का नाम- बायो सीएनजी प्लांट
- » कंपनी का नाम- नासिक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी
- » लागत- 30 करोड़ रुपए
- » डेडलाइन- 15 माह
- » प्लांट का क्षेत्रफल- 6 एकड़
- » कितना कचरा- 200 टन गीला कचरा प्रतिदिन
- » नगर निगम का खर्च- एक रुपए नहीं
- » निष्पादन में बचने वाला निगम का खर्च-2.43 करोड़ रुपए
- » यूनिडो से मिलने वाला अनुदान- 10.50 करोड़ रुपए
- » गैस का उपयोग- बीसीएलएल की बसों के संचालन में
- » नगर निगम को कितने में मिलेगी- बाजार मूल्य से पांच रुपए कम में
- » कितना कंपोस्ट बनाया जाएगा- 20 टन
- » कितने वर्षों का अनुबंध- 20 वर्ष

मप्र में घट रही खेतों की मिट्टी की उर्वरता

» खेतों की मिट्टी में सल्फर, जिंक व पोटाश की कमी

» प्रदेशभर में दलहनी फसलों का उत्पादन घटा

भोपाल। फसलों के उत्पादन में अब तक सात कृषि कर्मण अवार्ड पा चुके मप्र के खेतों की मिट्टी में सल्फर, जिंक और पोटाश की मात्रा कम होती जा रही है। इससे खेतों की उर्वरता घट रही है। इसका सबसे अधिक असल दलहनी फसलों के उत्पादन पर पड़ रहा है। कृषि विभाग के अनुसार, मालवा, निमाड़, ग्वालियर, चंबल और महाकोशल क्षेत्र की मिट्टी सबसे अधिक प्रभावित हुई है।

वैज्ञानिकों का कहना है कि रबी व खरीफ सीजन की फसलों की पैदावार में पिछड़ रहे जिलों की कृषि भूमि को जल्द ही पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हुई तो 2022 तक फसलों की पैदावार दोगुना करने का अभियान सफल नहीं हो पाएगा। इसका सीधा असर किसान की सालाना आय पर देखने को मिलेगा। इसकी वजह है कि वर्ष 2018 के बाद से ही केंद्र सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को बंद कर दिया। किसान अपने खेतों की मिट्टी की जांच नहीं करा पा रहे। इससे उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा कि उनके खेतों की मिट्टी में कौन-कौन से पोषक तत्वों की कमी बढ़ रही है। इसके लिए केन्द्र सरकार को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को उसके मूलस्वरूप में फिर से जिंदा करने की जरूरत होगी।

कमी पूरी करने में कम रुचि

कृषि विभाग के सूत्रों का कहना है कि मालवा को छोड़कर अन्य क्षेत्रों के किसान खेती में पोटाश तत्व की कमी पूरी करने में कम रुचि लेते हैं। यही कारण है कि फसलों में कीटव्याधि समस्या अधिक देखने को मिलती है। ग्वालियर-चंबल अंचल में किसान गेहूं, सरसों व बाजरा की फसल बहुतायत संख्या में करते हैं। इन सभी फसलों में यूरिया का उपयोग बहुतायत संख्या में होता है। किसानों के बीच यह भी धारणा है कि उर्वरक के अधिक उपयोग से उसका उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि उर्वरक का अधिक उपयोग मिट्टी के पोषक तत्व तेजी से खत्म कर रहा है। दूसरी समस्या यह है कि किसानों के पास खेत की मिट्टी जांचने की सुविधा न होने से उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा कि उनकी मिट्टी में कौन-कौन से पोषक तत्व कम हैं और उसकी कमी पूरी करने के लिए वे क्या करें।

पोरसा व जौरा में जिंक तत्व भी कम मिले

जिंक तत्व की कमी पोरसा व जौरा ब्लॉक में कम पाई गई है। जिंक की कमी के कारण पौधे छोटे रह जाते हैं। जिंक तत्व की कमी को 25 किलो प्रति हैक्टेयर कार्बनिक उर्वरक डालकर पूरा किया जा सकता है। जौरा इलाके के गांवों की जमीन में नाइट्रोजन तत्व 80 से 85 फीसदी कम पाया गया है। फॉस्फोरस तत्व भी लो टू मीडियम स्थिति में है।

आईसीएआर के स्थापना दिवस पर पढ़ा जागरुकता का पाठ

वैज्ञानिकों ने तकनीकी मार्गदर्शन में कराया पौधरोपण

टीकमगढ़। कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ द्वारा आईसीएआर की स्थापना दिवस के अवसर एवं अमृत महोत्सव के तहत गत दिवस ग्राम हसगोरा व नंदनपुर विकासखंड जतारा में जलवायु समुत्थानुशील कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार परियोजना के द्वारा हर मेड़ पर पेड़ विषय पर प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बीएस किरार, डॉ. एसके सिंह डॉ. आरके प्रजापति, जयपाल छिगारहा की उपस्थिति में 32 किसानों को 525 पौधे आम, अमरूद, नीबू, मुनगा, आंवला और कटहल का वितरण किया गया। साथ ही आम के पौधों का किसानों के खेत में वैज्ञानिकों के तकनीकी मार्गदर्शन में पौधरोपण कराया गया। यही नहीं, कृषक संगोष्ठी में किसानों को वैज्ञानिकों द्वारा पौधरोपण की वैज्ञानिक तकनीक के बारे में विस्तार से बताया गया। तकनीक अंतर्गत पौधों से पौधों एवं कतार से कतार की दूरी, गड्ढे का आकर व खाद की मात्रा की तकनीकी जानकारी दी गई। साथ ही पौधरोपण से पर्यावरण पर होने वाले सकारात्मक पहलुओं पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया। जैसे पेड़-पौधे जीव-जंतु व अजैविक तत्व- जलवायु प्रकाश इत्यादि सभी प्रकृति की रचना करते हैं। किसानों को बताया गया कि पेड़ हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं। फलदार पौधे पर्यावरण में सुधार के साथ-साथ किसानों की आय दोगुनी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसानों को बताया गया कि अनाज की खेती के साथ-साथ फलों की खेती भी वैज्ञानिक ढंग से की जा सकती है जिससे परिवारिक आय में बृद्धि एवं सेहत पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। डॉ. बीएस किरार द्वारा प्रत्येक पौधे की उपयोगिता एवं महत्वता पर भी प्रकाश डाला गया। साथ ही पौधरोपण के साथ-साथ पशुपालन किस तरह फायदेमंद होगा यह भी बताया गया। कार्यक्रम के दौरान डॉ. एसके सिंह एवं जयपाल छिगारहा द्वारा किसानों को फलदार के बीज में ली जाने वाली सब्जियों एवं फसलों के बारे में जानकारी दी गई। ताकि किसानों को एक फसल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। खेती के बारे में समझाया गया और आने वाले प्राकृतिक घटना जैसे असमय बरसा, ओलावृष्टि और आगजनी जैसी घटना आदि से किसानों को होने वाले नुकसान को विवधिकृत एवं अंतरवर्तीय खेती से कम किया जा सकता है।

- मखाना की खेती करने वाला मप्र का पहला जिला बालाघाट
- कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव में आधा एकड़ में प्रयोग सफल
- शुरुआत में जिले के छह किसान करेंगे मखाने की खेती
- मखाना की खेती देखने कलेक्टर दीपक आर्य पहुंचे गांव
- बिकता है 400 रुपए किलो से 800 रुपए प्रति किलो तक

बिहार का मखाना बालाघाट के किसानों को बनाएगा आत्मनिर्भर

रफी अहमद अंसारी, बालाघाट

नमकीन हो या व्रत का फलाहार मखाना के बिना इनकी कल्पना नहीं की जा सकती। दुनिया में सबसे ज्यादा मखाना उत्तर बिहार में पैदावार होती है। यहां के मधुबनी, दरभंगा सहित अन्य जिलों में दुनिया की कुल खपत का सबसे बड़ा हिस्सा पैदा होता है।

देश की कुल खपत का 90 फीसदी मखाना भारत में पैदा होता है जिसमें से 80 प्रतिशत की भागीदारी उत्तर बिहार के जिलों की है। लेकिन अब ऐसा कतई नहीं है। चूंकि मखाना की खेती करने वाला मध्यप्रदेश का पहला जिला बालाघाट हो गया है। तालाबों में मछली व सिंघाड़ा का उत्पादन होते हुए खूब सुना और देखा होगा। लेकिन अब कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव बालाघाट में पहली बार बिहार का मखाना छत्तीसगढ़ राज्य से बुलाया गया है। बालाघाट में एक

हजार पौधे लाकर आधा एकड़ में उत्पादन प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया था जो सफल हुआ है। उत्पादन में सफलता मिलने पर उन्नतशील किसानों को प्रशिक्षण देने चयनित कर लिया गया है। इससे किसानों की आर्थिक हालत में सुधार होगा ही और उनके लिए वरदान भी साबित होगा। मखाना नकद आय देने वाली फसल होने के साथ ही औषधि के रूप में उपयोगी है, इसीलिए बाजार में अधिक दाम में बिकता है।

इसका रखा जाएगा ध्यान

- उथले और कम पानी वाले खेत व तालाबों को उपयुक्त माना गया है।
- हाइब्रिड प्रजाति स्वर्ण वैदेही ने उत्पादन के साथ मुनाफा भी बढ़ाया है।
- खेत और तालाब में दो से ढाई फीट पानी होना चाहिए।
- दिसंबर से जनवरी के बीच इसके बीज लगाए जाते हैं।
- एक हेक्टेयर में करीब 80 किलो बीज लगता है।
- अप्रैल माह में मखाने में फूलने लगता है।
- इसका फूल-तीन चार दिन तक रहता है।
- इसी बीच इसमें बीज भी पड़ने लगता है।
- जून से जुलाई माह में 24-48 घंटे इसके फल पानी की सतह पर उतराते हैं। फिर वे नीचे जम जाते हैं।
- इसके फल कांटेनुमा कवच से ढंके होते हैं, जिनके कांटे गलने में एक से दो माह का समय लगता है। सितंबर अक्टूबर माह में इसे नीचे की सतह से निकाला जाता है।

मखाना देखने पहुंचे कलेक्टर

चयनित किसानों में से एक किसान अरविंद गाड़ेश्वर ग्राम बोट्टे विकासखंड लालबर्रा हैं। इनके खेत में बिहार की फसल मखाना कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा लगायी गयी है। इस फसल को देखने जिले के कलेक्टर दीपक आर्य और आईएएस एसडीएम बैहर तन्मेय वशिष्ट शर्मा भी हाल ही में गांव पहुंचे थे। इस दौरान कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के साथ उपसंचालक कृषि विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ.आरएल राऊत ने कलेक्टर को बताया कि मखाना एक जलीय फसल है, जो कि 1-2 फीट पानी में उगायी जा सकती है। किसान धान के खेत में फसल का रोपण कर 8-10 क्विंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। फसल में उत्पादन लागत अत्यंत कम है। प्रति एकड़ लागत निकालकर किसान को 40 हजार से 50 हजार रुपए तक की आय हो सकती है। जिले में तीन गांव बोट्टे (लालबर्रा), कोस्ते एवं नवशी (किरनापुर) के किसानों के खेत में यह फसल प्रयोग स्वरूप की गयी है।

सफल रहा प्रयोग

कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव विज्ञानियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले में बिहार से मखाना पहली बार बुलाए गए। यहां से कृषि विज्ञान केंद्र में जनवरी-फरवरी में पौधे लाकर इसका उत्पादन शुरू किया गया। इसके बाद उत्पादन सफल होने पर बालाघाट के जिले के रामपायली, आवलाझरी, बोटेहजारी में दो-दो किसानों को मखाने की खेती करने प्रशिक्षण दिया जाएगा।

मखाने के गुण

मखाना 500 से 700 रुपए किलो से भी अधिक बिकता है। इसके उत्पादन की एक विशेषता यह भी है कि इसमें लागत बहुत कम आती है। मखाना में प्रोटीन, विटामिन बी, वसा, कैल्शियम और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस कारण औषधि के रूप में इसे रामबाण माना गया है।

जिले का वातावरण अनुकूल

मखाने की फसल के लिए गर्म जलवायु का वातावरण चाहिए होता है। बालाघाट जिला भी इसी जलवायु के अंतर्गत आता है। यही वजह है कि बालाघाट का वातावरण इसके लिए अनुकूल है।

खेतों के लिए उपयुक्त

जिले में ज्यादातर किसान धान के लिहाज से खेतों को छोटी-छोटी बंधी के रूप में तैयार किए हुए हैं। जिनमें वर्षभर तालाब की तरह पानी को भरकर रखा जा सकता है। ऐसे खेत तालाब के रूप में मखाने के उत्पादन के लिए उपयुक्त है।

इनका कहना है

कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव में छत्तीसगढ़ के धमतरी से एक हजार पौधे लाकर प्रयोग के तौर पर इसका उत्पादन शुरू किया गया था जो सफल रहा। इसीलिए जिले के छह किसानों को चिन्हित किया गया है। यह नकदी की फसल है। इससे किसानों की आर्थिक हालत में सुधार आएगा। मखाना औषधि के रूप में ज्यादा काम आता है।

डॉ. आरएल राऊत, प्रमुख विज्ञानी, कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव बालाघाट

दरभंगा में वर्ष 2002 में स्थापित इस रिसर्च सेंटर में लगातार मखाने की हाईब्रिड प्रजाति के साथ, कम लागत में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन और मखाना में पोषक तत्वों से जुड़े रिसर्च चलते हैं। मखाने की पहली हाईब्रिड प्रजाति स्वर्ण वैदेही की खोज इसी सेंटर में हुई है। अब दूसरे राज्यों के भी किसान इससे जुड़ रहे हैं और पहली पैदावार से ही प्रॉफिट कमा रहे हैं।

डॉ. मनोज कुमार, कृषि वैज्ञानिक, मखाना रिसर्च सेंटर दरभंगा

तीन चरणों में होंगे पंचायत चुनाव

आयोग ने शुरू की तैयारीः नगरीय निकाय चुनाव दो चरणों में होंगे

पहले चरण में 155, दूसरे में 192 निकाय के लिए डाले जाएंगे वोट

प्रशासनिक संवाददाता, भोपाल

कोरोना की दूसरी लहर के थमते ही एक बार फिर से नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। प्रदेश की 407 नगरीय निकाय में से 347 में चुनाव होने हैं। चुनाव दो चरणों में होंगे। पहले चरण में 155 और दूसरे चरण में 192 नगरीय निकायों में मतदान कराया जाएगा।

वहीं पंचायत चुनाव को 3 चरण में करवाए जाने की बात कही गई। त्रि-स्तरीय पंचायतों में पंच के 3 लाख 77 हजार 551, सरपंच के 23 हजार 912, जनपद पंचायत सदस्य के 6 हजार 833, जिला पंचायत सदस्य के 904, उप सरपंच के 23 हजार 912, जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के 313 और जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के 52 पदों का निर्वाचन कराया जाएगा। यह जानकारी चुनाव को लेकर हुई आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग की समीक्षा बैठक में सामने आई। बैठक में निर्देश दिए गए कि निर्वाचन से संबंधित जो कार्रवाई शेष है, उसकी सूची बनाएं और प्रत्येक काम समय पर करें। तैयारी पूरी होते ही आम निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने आगामी चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण और वैक्सीनेशन की स्थिति को देखते हुए अब आम निर्वाचन करवाया जाना संभव है। कोरोना के कारण पहले से ही चुनाव बहुत लेट हो चुके हैं। पहले नगरीय निकायों के चुनाव करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नई अमिट स्याही खरीदने के आदेश जल्द जारी करें। नगरीय निकायों में बनने वाले स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की व्यवस्था करें। कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन हर स्तर पर किया जाए।

यह है मप्र की स्थिति

गौरतलब है कि प्रदेश के 407 नगरीय निकायों में से 307 का कार्यकाल 25 सितंबर 2020 को समाप्त हो चुका है। 8 नगरीय निकायों का कार्यकाल जनवरी और फरवरी 2021 में पूरा हुआ। त्रिस्तरीय पंचायतों में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल भी मार्च 2021 में समाप्त हो चुका है। नवगठित 29 नगर परिषदों में भी चुनाव होने बाकी है।

कहां कितने मतदाता

एमपी नगरीय चुनाव में कुल 1 करोड़ 69 लाख 16 हजार 83 मतदाता हैं। इनमें पुरुष 86 लाख 81 हजार 912, महिला 82 लाख 32 हजार 897 और थर्ड जेंडर 1274 हैं। वहीं, पंचायत निर्वाचन में कुल मतदाता 3 करोड़ 92 लाख 81 हजार 301 हैं। इनमें पुरुषों की संख्या 2 करोड़ 2 लाख 45 हजार 823, महिलाओं की संख्या एक करोड़ 90 लाख 34 हजार 424 और थर्ड जेंडर की संख्या 1054 है।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, गोपाल दास बंसल-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
हरदा, राजेन्द्र बिल्लोरे-9425643410
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948827
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पताः- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादक- **सतीश उपाध्याय, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)